

## अमेरिका की नीतियों में परविरतन का भारत पर प्रभाव

### प्रलिमिस के लिये:

पेरसि समझौता, वैश्व अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वैश्वकि न्यूनतम कर, H-1B वीजा, ग्रीनहाउस गैसें, जीवाशम ईंधन, वैश्वकि दक्षणि, आरथकि सहयोग और विकास संगठन, टैक्स हेवेन, कवाड गठबंधन, BRICS

### मेन्स के लिये:

अमेरिकी नीतियों में परविरतन और भारत पर इसका प्रभाव, जन्मसदिध नागरिकता, नीतिगत परविरतन के पश्चात् वैश्वकि जलवायु कार्यवाही, कराधान और वैश्वकि अरथव्यवस्था

सरोत: द हॉट्स

### चर्चा में क्यों?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कई कार्यपालक आदेशों पर हस्ताक्षर किये हैं, जिनमें जन्मसदिध नागरिकता समाप्त करना, पेरसि समझौते से हटना, वैश्व अंतर्राष्ट्रीय संगठन (WHO) से बाहर निकलना और वैश्वकि कॉर्पोरेट न्यूनतम कर (GCMT) समझौते को खारज़ि करना शामिल है।

- इन नियमों का भारत, जलवायु नीति और अमेरिका में भारतीय पेशेवरों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

### जन्मसदिध नागरिकता के नियम का क्या प्रभाव है?

- अमेरिका में जन्मसदिध नागरिकता: अमेरिका में दो प्रकार की जन्मसदिध नागरिकता है- वंश-आधारति और जन्मस्थान-आधारति (jus soli) (जन्मस्थान-आधारति), जिसके अंतर्गत माता-पति की राष्ट्रीयता को दृष्टिगति न रखते हुए अमेरिका की धरती पर जन्म लेने वाले व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की जाती है।
- कार्यपालक आदेश: आदेश के अनुसार गैर-नागरिक (अन्यदेशीय) माता-पति से जन्म लेने वाले बच्चे अमेरिकी अधिकैरता के अध्यधीन नहीं हैं और इसलिये वे स्वतः नागरिकता के योग्य नहीं हैं।
  - कार्यपालक आदेश का एक मुख्य उददेश्य "बरथ ट्रूज़िम" को कम करना है, जहाँ महलिएँ अपने बच्चों के लिये स्वतः नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्हें जन्म देने हेतु अमेरिका की यात्रा करती हैं।
  - यह नीतिविशेष रूप से भारत और मैक्सिको जैसे देशों के प्रवासियों को प्रभावित करेगी, जहाँ बरथ ट्रूज़िम प्रचलित है।
- प्रभाव:
  - H-1B वीजा धारकों पर प्रभाव: भारतीय H-1B वीजा धारकों और ग्रीन कारड आवेदकों के अमेरिका में जन्मे बच्चों की नागरिकता स्वतः समाप्त हो सकती है, जिससे प्रवासियों के लिये अनिवार्यता की स्थितिजितपन हो सकती है।
    - मशिरति नागरिकता वाले प्रवासियों को स्वजन से अलगाव का सामना करना पड़ सकता है या उन्हें अमेरिका में अपने भविष्य पर पुनर्वाचार करने के लिये विविध होना पड़ सकता है।
    - इस नीतिगत बदलाव से कुशल श्रमिकों द्वारा दीर्घावधि का प्रवासन करने और प्रवास नियोजन किये जाने को लेकर हतोत्साहित हो सकते हैं।
    - भारतीय नागरिक कनाडा, ब्रॉन्टन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड जैसे देशों में प्रवास का विकल्प चुन सकते हैं, जहाँ आवर्जन नीतियाँ अधिक अनुकूल हैं।
  - नियमों में वृद्धि: अमेरिका में लगभग 7.25 लाख अवैध भारतीय नागरिकों को नियमों का खतरा बढ़ गया है।
  - कानूनी चुनौतियाँ: जन्मसदिध नागरिकता का नियम अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के विपरीत है, जो अमेरिकी धरती पर जन्मे सभी लोगों को नागरिकता की गारंटी प्रदान करता है। न्यायालय में चुनौती दिये जाने की संभावना है।
  - अमेरिका पर आरथकि प्रभाव: कुशल प्रवासी नवाचार, स्वास्थ्य सेवा और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
    - ऐसी नीतियों से अमेरिका में प्रतिभाओं की कमी हो सकती है तथा भारतीय पेशेवरों पर नियमों का व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।

## पेरसि समझौते से अमेरिका के अलग होने के क्या नहितारथ हैं?

- पेरसि समझौता: वर्ष 2015 में पेरसि में **संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP21)** में 196 देशों (भारत सहित) द्वारा अपनाया गया, यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फरमवरक कन्वेंशन (UNFCCC) के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्वकि समझौता है।
  - इसका उददेश्य वैश्वकि तापमान को पूर्व-औद्योगिक स्तर से  $1.5^{\circ}\text{C}$  तक सीमित रखना है, तथा इसे  $3.6^{\circ}\text{F}$  ( $2^{\circ}\text{C}$ ) से नीचे रखने का लक्ष्य है।
  - राष्ट्रों को अधिकाधिकि महत्त्वाकांक्षी उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्य निरिधारित करने के लिये प्रतोत्साहित करना।
  - इसमें अमेरिका सहित वाकिसहित देशों से यह अपेक्षा की गई है कि विकासशील देशों में जलवायु अनुकूलन और शमन प्रयासों के लिये वित्तीय सहायता देना।
- अमेरिकी वापसी के कारण: ट्रंप ने कहा कि **पेरसि समझौता** अमेरिकी मूलयों को प्रतबिंబित नहीं करता है और करदाताओं के वित्त को उन देशों की ओर पुनरनिर्देशित करता है जिन्हें वित्तीय सहायता की "आवश्यकता नहीं है या वे इसके पात्र नहीं हैं।"
- नहितारथ: **गरीनहाउस गैसों** के दूसरे सबसे बड़े उत्सर्जक के रूप में अमेरिका, उत्सर्जन को कम करने के वैश्वकि प्रयासों में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिता है।
- पेरसि समझौते से अलग होने से अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त पर प्रभाव पड़ेगा, तथा भारत सहित विकासशील देशों में शमन और अनुकूलन प्रयासों के लिये धन में कटौती होगी।
- नजीरी **जलवायु वित्तपोषण** में कटौती, जो कि अमेरिका से अत्यधिकि प्रभावति है, नवीकरणीय ऊर्जा और हरति परियोजनाओं के लिये संसाधनों को सीमित कर सकती है।
- इसके अतिरिक्त, **जीवाशम ईंधन** पर अमेरिका के ध्यान और ऊर्जा विनियमों को वापस लेने से चार वर्षों में 4 बलियन टन अतिरिक्त उत्सर्जन हो सकता है, जिससे वैश्वकि जलवायु के समक्ष चुनौतियाँ और भी बढ़ जाएंगी।

## जलवायु वित्त

जलवायु वित्त का तात्पर्य जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध शमन और अनुकूलन संबंधी कार्यों का समर्थन करने के लिये सार्वजनिक/निजी/वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोतों से प्राप्त स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण से है।

### जलवायु वित्त के सिद्धांत

- ④ प्रदूषणकर्ता भुगतान करता है,
- ④ 'समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारी और संबंधित क्षमताएँ' (CBDR-RC)

### UNFCCC द्वारा

#### समन्वित बहुपक्षीय जलवायु कोष

- ④ वैश्वक पर्यावरण सुविधा (GEF): वित्तीय तंत्र की संचालन इकाई (1994)
- ④ क्योटो प्रोटोकॉल (2001):
  - ④ अनुकूलन कोष (AF): विकासशील देशों को अनुकूलन परियोजनाओं का पूर्ण स्वामित्व प्रदान करना।
  - ④ स्वच्छ विकास तंत्र (CDM): विकासशील देशों में उत्पर्जन-कटौती परियोजनाओं को पूर्ण करना।
- ④ हरित जलवायु कोष (GCF): वर्ष 2010 में स्थापित (COP 16)
  - ④ इसके अंतर्गत कोष- अल्प विकसित देश कोष (LDCF) और विशेष जलवायु परिवर्तन कोष (SCCF)
- ④ दीर्घकालिक जलवायु वित्त:
  - ④ कानकुन समझौता (वर्ष 2010): लघु और दीर्घकालिक में धन एकत्रित करना तथा उपलब्ध कराना।
  - ④ पेरिस समझौता (वर्ष 2015): विकसित राष्ट्र वर्ष 2025 तक कम-से-कम 100 बिलियन डॉलर/वर्ष का नवीन सामृहक लक्ष्य स्थापित करने पर सहमत हुए।
- ④ लॉस एंड डैमेज फंड (2023) (COP27 और COP28): जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सबसे कमज़ोर और प्रभावित देशों को वित्तीय सहायता करना।

### विश्व बैंक के

#### अधीन जलवायु निवेश कोष (CIF)

- ④ स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष
- ④ सामरिक जलवायु कोष

#### जलवायु वित्त के संबंध में भारत की पहल

कोष	उद्देश्य उद्देश्य
गांधीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (NAFCC) (2015)	कमज़ोर भारतीय राज्यों के लिये
राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (2010-11)	स्वच्छ ऊर्जा को आगे बढ़ाना (ऐंडोगिक कायले के उपयोग पर प्रारंभिक कार्बन टेक्स के साथ प्रारंभ करना)
राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (2014)	आवश्यक और उपलब्ध कोष के बीच अंतर को ख़त्म करना
अभीष्ट राष्ट्रीय निधीरित अंशदान (INDCs) (2015)	UNFCCC के तहत अपनाए गए राष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी लक्ष्य
जलवायु परिवर्तन वित्त इकाई (2011)	वैश्वक जलवायु वित्त मुद्रों पर नेतृत्व करता है

### जलवायु वित्त के समक्ष चुनौतियाँ

- ④ NDCs के तहत राष्ट्रीय आवश्यकताओं और जलवायु वित्त के बीच अंतर (Gap) होना,
- ④ अल्प विकसित देशों को बहुपक्षीय जलवायु कोष से प्रति व्यक्ति के हिसाब से न्यूनतम स्वीकृत धनराशि मिलना,
- ④ स्वीकृतियों की धीमी दर,
- ④ व्यवहार्यता-अंतर वित्त पोषण हासिल करने में विफल होना।



Drishti IAS

## WHO से अमेरिका के अलग होने के क्या प्रभाव होगा?

- अमेरिका के पीछे हटने के कारण: ट्रंप ने कोविड-19 महामारी से नपिटने में WHO की लापरवाही, त्वरति सुधारों को लागू करने में वफ़िलता और राजनीतिक प्रभाव, विशेष रूप से चीन के प्रति संवेदनशीलता को अमेरिका के पीछे हटने के कारणों के रूप में उद्धृत किया।
- चीन की बड़ी जनसंख्या के बावजूद, अमेरिका द्वारा चीन की तुलना में दर्ये जाने वाले असंगत वित्तीय योगदान पर चाति व्यक्त की गई।

- अमेरिका ने WHO के कुल वित्तिपोषण में लगभग 20% का योगदान दिया, जो कनिरिधारति एवं सैवैच्छकि दोनों प्रकार से था।
- **प्रभाव:**
  - WHO पर प्रभाव: अमेरिका के हटने से वित्तिपोषण में कमी आएगी, जो पोलियो उन्मूलन और महामारी की तैयारी सहति वैश्वकि स्वास्थ्य कार्यकर्मों को बाधित कर सकती है।
    - कार्यकारी आदेश में सभी अमेरिकी कर्मियों और ठेकेदारों को वापस बुलाने का आदेश दिया गया, जिसके परणिमस्वरूपैक्सीन अनुसंधान, रोग नियंत्रण और स्वास्थ्य नीतियोंसे प्रमुख क्षेत्रों में वैशिष्ट्यज्ञता का नुकसान हुआ, जिससे वैश्व स्तर पर WHO की सलाहकार भूमिका कमज़ोर हो गई।
  - अमेरिका के लिये घरेलू नहितिरथ: WHO से हटने से अमेरिकियों की वैश्वकि स्वास्थ्य खुफिया जानकारी तक पहुँच सीमित हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों पर अमेरिका का प्रभाव कम हो सकता है।
  - भारत पर प्रभाव: वैश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका के बाहर नकिलने से भारत के स्वास्थ्य कार्यकरम धीमे हो सकते हैं, जिसमें ह्यूमन इम्यूनोडिफिसिएंसी वायरस (HIV) और तपेदकि जैसी बीमारियों पर कथि जाने वाले प्रयास भी शामिल हैं।
    - वैश्व स्वास्थ्य संगठन के वित्त पोषण और वैशिष्ट्यज्ञता में कमी के कारण, भारत और अन्य ग्लोबल साउथ देशों से वैश्वकि स्वास्थ्य में बड़ी भूमिका नभिने की उम्मीद की जा रही है, तथा भारत विकासशील देशों के बीच अधिकि सहयोग की वकालत करने वाले एक नेता के रूप में उभर रहा है।

## वैश्वकि कॉर्पोरेट न्यूनतम कर समझौते को अमेरिका द्वारा अस्वीकार कथि जाने का क्या प्रभाव होगा?

- **GCMT समझौता:** आरथकि सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) के ढाँचे के तहत कथि गए इस समझौते में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिये ग्लोबर्ड मॉडल नियमों के तहत वैश्वकि न्यूनतम कर (GMT) दर निरिधारति की गई।
  - यह सुनिश्चिति करता है कथि प्रत्येक क्षेत्राधिकार में न्यूनतम कर का भुगतान करें, लाभ स्थानांतरण को कम करें और कॉर्पोरेट कर दरों में "रेस टू द बॉटम" को समाप्त करें, जिसका उद्देश्य देशों को व्यापार को आकर्षित करने के लिये कर दरों में कटौती करने से रोकना है, जिसके परणिमस्वरूप प्रायः न्यूनतम कर राजस्व प्राप्त होता है।
  - अपने दो-सतंभीय समाधान के साथ इस समझौते का उद्देश्य कर चोरी, टैक्स हेवेन पर अंकुश लगाना और वैश्वकि कर प्रतिसिप्रदधा को स्थिरि करना है।
    - **सतंभ 1:** यह घटक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लाभांश को उन क्षेत्रों में पुनः आवंटति करने पर केंद्रति है जहाँ से वे राजस्व सृजति करती हैं।
    - **सतंभ 2:** इसमें 15% **GMT** दर निरिधारति की गई है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चिति करना है कि कंपनियोंकरों का उचति भुगतान करें, चाहे वे कहीं भी परचिलन करती हों।
- अमेरिकी अस्वीकृति के कारण: राष्ट्रपतिट्रिंग ने तरक दिया कि 15% की **GMT** दर अमेरिकी संप्रभुता और प्रतसिप्रदधा का उल्लंघन करती है, और दावा कथि कि इससे अमेरिकी प्रणाली की तुलना में अधिकि करों के कारण अमेरिकी व्यवसायों को नुकसान होगा।
  - वर्ष 2017 के टैक्स कट्स एंड जॉब्स एक्ट के तहत, अमेरिका में 10% वैश्वकि न्यूनतम कर था।
- **प्रभाव:**
  - वैश्वकि सहमतपिर प्रभाव: समझौते से अमेरिका के हटने से वैश्वकि कर नियमों पर आम सहमततिक पहुँचने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में बाधा आ सकती है।
  - भारत पर प्रभाव: वैशिष्ट्यज्ञों का सुझाव है कि वैश्वकि कर समझौते से अमेरिका के बाहर होने से भारत की कर नीतियों एवं कर संग्रहण प्रणालीयों पर कोई वैश्व प्रभाव नहीं पड़ेगा।
    - भारत ने "प्रतीक्षा करो और देखो" का दृष्टिकोण अपनाया है तथा GloBE नियमों से संबंधित वैशिष्ट कानून बनाने से परहेज कथि है।
    - परणिमस्वरूप, देश का कर प्रदिव्य फलिहाल अप्रभावति बना हुआ है।

## भारत कसि प्रकार उभरती अमेरिकी नीतियों के आलोक में सामंजस्य स्थापति कर सकता है?

- **वकालत और कूटनीति:** भारत को अपने आपरवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिये सकरथि रूप से कूटनीतिक उपायों को अपनाना चाहयि तथा यह सुनिश्चिति करना चाहयि कि भारतीयों को विकसित होती अमेरिकी नीतियों के तहत संरक्षित कथि जाए।
  - अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने से ऐसी नीतियों की वकालत करने में मदद मलि सकती है जो भारतीय प्रवासियों के लिये अधिकि समावेशी और सहायक हों जिससे अधिकि नष्टिपक्ष वातावरण सुनिश्चित हो सके।
  - अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्राउड गरबंधन को मज़बूत करने से क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ाने के साथ-साथ चीन के प्रभाव को संतुलित कथि जा सकता है।
- **जलवाय कार्यवाही में तेज़ी लाना:** भारत को जलवाय नेतृत्व प्रदरशति करने के लिये राष्ट्रीय सौर मशिन और राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति, 2018 के तहत अपने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में तेज़ी लानी चाहयि।
  - युरोपियन युनियन, जापान और पेरेसि समझौते के अन्य हस्ताक्षरकरताओं के साथ सहयोग करने से नवीकरणीय ऊर्जा विकास को बढ़ावा देने के लिये हरति परयिजनाओं के लिये वैकल्पिक वित्तिपोषण सुरक्षिति करने में मदद मलि सकती है।
- **वैश्वकि स्वास्थ्य क्षेत्र में भूमिका:** भारत अपनी फारमास्युटिकिल एवं स्वास्थ्य सेवा वैशिष्ट्यज्ञता का लाभ (जैसा कि कोविड-19 वैक्सीन कूटनीतिके दौरान प्रदरशति कथि गया है) उठा सकता है, ताकि वैश्व स्वास्थ्य संगठन में अमेरिका की कम भागीदारी से उत्पन्न अंतराल को भरा जा सके।
  - वैश्व स्वास्थ्य संगठन में प्रमुख पदों पर अधिकि भारतीय पेशेवरों की नियुक्तिपिर बल देकर, भारत वैश्वकि स्वास्थ्य प्रशासन में अपना नेतृत्व बढ़ा सकता है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों को आकार देने में अपनी स्थिति भिजबूत कर सकता है।

- बहुपक्षीय मंचों पर कार्रव करना: अमेरिकी नीतिगत बदलावों से प्रभावित देशों (जैसे यूरोपीय संघ और **BRICS** सदस्यों) के साथ साझेदारी करके, सामूहिक कार्रवाही हेतु गठबंधन बनाया जा सकता है।

**प्रश्न:**

प्रश्न: वैश्विक शासन एवं भारत के हतों के संबंध में अमेरिकी नीतिगत बदलावों के व्यापक नहितारथ हैं। इनके प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण करते हुए सुझाव दीजिये कि भारत इस संदर्भ में रणनीतिक रूप से किस प्रकार प्रतिक्रिया दे सकता है।

और पढ़ें: [भारत-अमेरिका संबंध](#)

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा , वगित वर्ष प्रश्न

**प्रश्न:**

प्रश्न. 'भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच संबंधों में खटास के प्रवेश का कारण वाशिंगटन का अपनी वैश्विक रणनीतिमें अभी तक भी भारत के लिये किसी ऐसे स्थान की खोज करने में वफिलता है, जो भारत के आत्म-समादर और महत्त्वाकांक्षा को संतुष्ट कर सके।' उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिये। (2019)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/impact-of-us-policy-shifts-on-india>

